



सच, सिर्फ सच

गुरुवार, 17 जुलाई, 2025 लखनऊ, महानगर, वर्ष 20, अंक 193, पेज 16, 3.50 रुपये

बॉयस ऑफ लखनऊ

www.facebook.com/volepaper voiceoflucknow@gmail.com www.voiceoflucknow.com



सेंसेक्स में 64 अंकों की उछाल

स्थानीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। सीमित कारोबार में बीएसई सेंसेक्स मामूली 64 अंक बढ़कर 82,634.48 अंक पर बंद हुआ।

वित्तमंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला, शिकायतकर्ता पर जुर्माना

दिल्ली की एक अदालत ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

ड्रोन में आत्मनिर्भरता जरूरी : सीडीएस

एजेंसी नयी दिल्ली। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि हाल के वैश्विक संघर्षों में यह बात सामने आई है कि कैसे ड्रोन युद्ध के रणनीतिक संतुलन को गैर आनुपातिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ड्रोन और काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (सी-यूएस) (मानवहित हवाई रोधी प्रणाली) में आत्मनिर्भरता भारत के लिए रणनीतिक रूप से अनिवार्य है। यहाँ मानेकशां सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनरल चौहान ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया है कि क्यों स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई प्रणालियाँ (यूएस) और सी-यूएस हमारे क्षेत्र और हमारी जरूरतों



के लिए महत्वपूर्ण हैं। यूएवी और सी-यूएस के क्षेत्र में विदेशी ओईएम से वर्तमान में आयात किए जा रहे महत्वपूर्ण घटकों के स्वदेशीकरण विषय पर थिंक टैंक सेंटर फॉर ज्वॉइंट वायुफेयर स्टडीज के सहयोग से एकिकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय (एचक्यू-आईडीएस) की मेजबानी में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह आयोजन हाल में भारत-पाकिस्तान

प्रदेश के 75 जिलों में विकसित होंगी आपदा प्रबंधन योजनाएं

आपदा प्रबंधन की दिशा में अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा उत्तर प्रदेश : योगी विशेष संवाददाता लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार की ओर से आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राज्य में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी, समन्वित, वैज्ञानिक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सम्पन्न हुआ। यह समझौता बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर यूएनडीपी की भारत प्रमुख एवं रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव एंजेला लुसीगी विशेष रूप से उपस्थित रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि आपदा प्रबंधन आज के समय की एक अनिवार्य प्रशासनिक प्राथमिकता है। तकनीकी दक्षता, प्रशिक्षण और पूर्व तैयारी के समन्वय से ही हम आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता को विश्वस्तरीय बनाएगी और शासन-प्रशासन को वैज्ञानिक ढंग से निर्णय लेने में समर्थ बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रयास उत्तर प्रदेश के आपदा न्यूनीकरण प्रयासों को नई दिशा देगा। इससे प्रदेश में जीवन, संपत्ति और अवसंरचना की रक्षा के लिए समेकित रणनीति पर कार्य करना अधिक सुगम होगा और आपदा प्रबंधन की दिशा में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा। यह



नयी दिल्ली। भारतीय सेना ने बुधवार को स्वदेशी रूप से विकसित किए गए आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण लद्दाख क्षेत्र में 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर किया गया। यह परीक्षण सेना ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया, जिन्होंने इस प्रणाली को विकसित किया है। परीक्षण के दौरान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने बहुत तेज गति से उड़ रहे हवाई लक्ष्यों पर सीधा प्रहार किया। यह परीक्षण बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किया गया। आकाश प्राइम सिस्टम अब भारतीय सेना की हवाई सुरक्षा की तीसरी और चौथी युनिट (रेंजिमेंट) का हिस्सा बनेगा। इसका मतलब है कि अब यह नई प्रणाली सेना की और दो टुकड़ियों में शामिल की जाएगी ताकि दुश्मन के हवाई हमलों से और बेहतर तरीके से रक्षा की जा सके। रक्षा अधिकारियों के अनुसार, इस प्रणाली ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इस समय पाकिस्तान की सेना द्वारा चीनी विमानों और तुर्किये के ड्रोन से

संक्षेप

ट्रक चालक को लूटने के आरोप में ग्यारह पुलिसकर्मी निलंबित

कानपुर। कानपुर में मवेशियों से भरे एक ट्रक के चालक और सहायक को लूटने के आरोप में पांच हेड कांस्टेबल समेत 11 पुलिसकर्मियों को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) योगेश कुमार ने बताया कि गत शनिवार को आरोपी पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर एक ट्रक का पीछा किया और कारकाल्डसमय उन्हें उसके सहायक मोहम्मद उजैर को हर पुलिसकर्मी को 500-500 रुपये देने के लिए मजबूर किया। आरोप लगाया गया है कि ऋषिगंज, हरिओम और अतुल सचान सहित सभी आरोपी पुलिसकर्मियों ने लक्ष्मण उर्फ लकी और उजैर के साथ मारपीट की, उनकी आंखों पर डंडे से वार किया और 10 हजार रुपये नकदी भी लूट ली। अधिकारियों ने बताया कि जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, उनको पहचान ऋषिगंज, अमीर हसन, प्रदीप कुमार, अजय कुमार ... शेष पृष्ठ 14 पर

सीएम मोहन यादव के ससुर का निधन

सुलतानपुर। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के ससुर ब्रह्मदीन यादव का उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे। ब्रह्मदीन यादव ने मंगलवार रात सुलतानपुर के विवेकानंद नगर क्षेत्र में अपने बेटे विवेकानंद यादव के आवास पर अंतिम सांस ली। विवेकानंद यादव ने बताया कि उनके पिता का पार्थिव शरीर मंगलवार की रात यहाँ से मध्यप्रदेश के रीवा के लिए एंबुलेंस से ले जाया गया जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भैरवपिता का स्वस्थ 27 जून की रात्रि में बिगड़ गया था। उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था।

किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी

पीएम धन-धान्य कृषि योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी, एनटीपीसी की निवेश सीमा बढ़ाकर की 20,000 करोड़

एजेंसी नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 जिलों में कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए सालाना 24,000 करोड़ रुपये के आवंटन वाली प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को बुधवार को मंजूरी दी। छह साल तक चलने वाली इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। यह योजना 2025-26 के बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए 100 जिलों के विकास की घोषणा के अनुरूप है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी दी। वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी को समाहित कर कार्यान्वित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग 1.7



सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को पूरे देश के लिए गर्व, गौरव और खुशी का क्षण बताया गया। इसमें कहा गया है कि इस यात्रा ने भारत की असीम आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में पारित संकल्प को पढ़ते हुए कहा, मंत्रिमंडल, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेसन पर अपने ऐतिहासिक 18 दिवसीय

मिशन के सफल समापन के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी का जश्न मनाने में राष्ट्र के साथ शामिल है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, इस योजना के क्रियान्वयन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान अगस्त में शुरू होगा। उन्होंने कहा हम इस योजना की अवदूब से लगू करेंगे, जब रबी की बुवाई शुरू होगी। चौहान ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में खाद्यान्न, बागवानी और दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के बावजूद राज्यों और जिलों के बीच उपज का अंतर है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर फसलों की कटाई के बाद अनाज भंडारण बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और किसानों के लिए दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। योजना के लिए 100 जिलों को पहचान कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम जग वितरण के तीन प्रमुख मानदंडों के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक राज्याकेंद्रशासित प्रदेश में जिलों की संख्या शुद्ध फसल क्षेत्र और परिचालन जोत के हिस्से पर आधारित होगी। हालांकि, प्रत्येक राज्य से कम-से-कम एक जिला इस योजना के लिए चुना जाएगा। बयान के मुताबिक, योजना के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समिति गठित की जाएगी। जिला धन-धान्य समिति द्वारा एक जिला कृषि एवं संबद्ध कार्यक्रम योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें प्रगतिशील किसान भी शामिल होंगे। जिला योजनाओं को फसल विविधीकरण, जल एवं मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और प्राकृतिक एवं जैविक खेती के विस्तार जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जाएगा। प्रत्येक धन-धान्य ... शेष पृष्ठ 14 पर

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर सेना का कड़ा प्रहार

एजेंसी श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को यह जानकारी दी। हीरानगर जम्मू जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर स्थित है और यहाँ पहले भी आतंकवादियों के साथ कई मुठभेड़े हो चुकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार रात को एक ग्रामीण ने दो संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि की सूचना सुरक्षाबलों को दी थी। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक इलाके में तलाशी अभियान जारी था। अभी तक संदिग्ध लोगों का कोई सुराग नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई भारतीय शस्त्र ... शेष पृष्ठ 14 पर

पौधरोपण से ही बनेगा पर्यावरणीय संतुलन

धामी ने याद दिलाया पंचामृत संकल्प, हर अवसर पर लगायें एक पौधा प्रमुख संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड के पारंपरिक पर्व हरेला के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा रोपकर प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम की थीम थी हरेला मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरेला केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यावरण चेतना का प्रतीक है। इस बार प्रदेशभर में लगभग पांच लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि वे चूष बन सकें। उन्होंने बताया कि वन विभाग के हर डिवीजन में 50 प्रतिशत फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। इस अभियान में स्वयंसेवी संगठनों, छात्र-छात्राओं, महिला समूहों और पंचायतों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचामृत संकल्प, नेट जीरो इमिशन, लाइफस्टाइल ... शेष पृष्ठ 14 पर



मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरेला केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यावरण चेतना का प्रतीक है।

प्रदेश के कई जिलों में बारिश बनी आफत

विशेष संवाददाता लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जारी मानसूनी बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बन गई है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बीते कई दिनों से रुक रुक कर मानसूनी बारिश जारी है। बृहस्पतिवार को विंध्य और बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी समेत कुल 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 19 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। साथ ही 58 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। बुधवार को प्रदेश के वाराणसी, सुलतानपुर, प्रयागराज और विंध्य क्षेत्र में अच्छी बारिश देखने को मिली। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक झारखंड के आसपास संकेद्रित अवदाब कमजोर पड़ने से एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है जो पूर्वी यूपी की ओर आगे बढ़ रहा है। बृहस्पतिवार को विंध्य, बुंदेलखंड और दक्षिणी यूपी में भारी बारिश संकेत है। बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, विजयनगर, अमरौहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन व आसपास के इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गयी है।



बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, विजयनगर, अमरौहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन व आसपास के इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गयी है।

आज का मौसम अधिकतम : 32.06 डिग्री न्यूनतम : 27.04 डिग्री

भीतर पढ़ें

- देश का आर्थिक पावर हाउस बन रहा है यूपी (पृष्ठ-02)
- उत्तर प्रदेश के युवा अब बन रहे आत्मनिर्भर (पृष्ठ-02)
- सोना का भाव 500 रुपये टूट, चांदी 1,000 गिरी (पृष्ठ-14)
- छोटे देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगायेंगे ट्रंप (पृष्ठ-14)
- चिली, पेरू से व्यापार समझौतों पर वार्ता अग्रस्त में (पृष्ठ-14)

छांगुर बाबा का नेटवर्क ध्वस्त!

लखनऊ। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन और नसरनी को बुधवार को लखनऊ उच्च कोर्ट में पेश किया। एटीएस टीम दोनों को सरोजिनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहाँ दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद दोनों को कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ले जाते समय छांगुर बाबा बोला- मैं बेकसूर हूँ। सूत्रों के अनुसार, एटीएस ने सात दिन की रिमांड अर्थात् खतम होने के बाद रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की है। ताकि छांगुर नेटवर्क से जुड़े और नामों ... शेष पृष्ठ 14 पर

देश का आर्थिक पावरहाउस बन रहा है यूपी : मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश लक्ष्य-उन्मुख राज्य, प्रदेश बड़ी छलांग लगाने को तैयार

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों के लिए यह विजन रखा है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत एक विकसित राष्ट्र बने। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने में उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश जैसी मिट्टी, खनन, विविध जलवायु, और पानी की उपलब्धता विश्व में कहीं और नहीं है। ये संसाधन उत्तर प्रदेश को कृषि का पावरहाउस बनाते हैं। योजना भवन में आयोजित विकसित राज्य-विकसित भारत @2047 पर एक उच्च स्तरीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उक्त बातें मुख्य सचिव मनोज



कुमार सिंह ने कही। इस कार्यशाला का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ उत्तर प्रदेश की दीर्घकालिक विकास रणनीति तैयार करना था।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा जेवर एयरपोर्ट के पास 50 हेक्टेयर में टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और पैकेजिंग सुविधाओं से युक्त एक कृषि निर्यात केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो बागवानी उत्पादों के कार्गो-आधारित निर्यात को बढ़ावा देगा और कृषि-लॉजिस्टिक्स में क्रांति लाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का दूसरा प्रमुख

ताकतवर क्षेत्र है इफ़ास्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन को मजबूत किए बिना विकसित देश की कल्पना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ओडीओपी), वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज पहला राज्य है जिसने 1 ट्रिलियन 25 सबसे गरीब परिवारों को लक्षित) जैसे पहल समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।। मुख्यमंत्री की सहमति से 30 करोड़ रुपये की लागत से बड़े स्कूल बनाए जा रहे हैं।

नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने डीडीपी जैसे उन्नत प्रदर्शक के डेटा गुणवत्ता और प्रगतिशील नियोजन मॉडल की सराहना की और कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। विश्व में 5वें सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र होने के नाते, उत्तर प्रदेश को विजन 2047

सोलर पॉवर प्लांट से रौशन होंगी टीएचआर इकाइयों

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओ द्वारा विभिन्न जिलों में राज्य सरकार के सहयोग से टेक होम राशन इकाईयों का संचालन किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो के संचालन मे महिलाओ की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने के निर्देश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिये गये हैं।

उप मुख्यमंत्री की पहल पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओ द्वारा संचालित इकाईयों पर सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कर विजली पर आने वाले व्यय को कम किया जा रहा है, इससे महिलाओ की आमदनी मे इजाफा हो रहा है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा रंजन द्वारा 49 टीएचआर इकाईयों पर 75 किलोवाट सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना

भाजपा ने पुलिस को निरंकुश कर दिया : अखिलेश यादव

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा ने पुलिस को निरंकुश कर दिया है। गरीबों को न्याय नहीं मिला रहा है। पुलिस प्रताड़ना और न्याय नमिलने से गरीब जान देने पर मजबूर है। जिस पुलिस पर लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी है उसी से पीड़ित होकर लोग आत्महत्या करने पर विवश हैं। जबसे भाजपा सरकार सत्ता में आयी है तब से पुलिस पर फर्जी एनकाउण्टर, वसूली, लूट तक में शामिल होनेके आरोप लग रहे है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा पर विवश हैं। 25 बसे भाजपा राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। चुनाव में दबाव बनाकर अपने पक्ष में फर्जी वोटिंग तक कराती है। मतदाताओं को डराती है। विरोधियों पर झूठे मुकदमे लगावाती है। क्या पुलिस का यह आचरण पुलिस सेवा नियमावली के विरुद्ध नहीं है? उन्होंने कहा कि भाजपा ने पुलिस तक को खराब कर दिया, जिसका खामियाजा प्रदेश की गरीब जनता भुगत रही है।

विधानसभा में एआई क्रांति की शुरुआत विधायकों को मिलेगा प्रशिक्षण

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का प्रशिक्षण शुरू करने की तैयारी है। यह प्रशिक्षण देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के प्रोफेसरों द्वारा प्रदान किया जाएगा। आगामी मानसून सत्र के मध्य या अंत में इस विशेष सत्र का आयोजन प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा और किसी भी सदस्य पर बाध्यकारी नहीं होगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विधानसभा के सदस्य एआई टूल को आसानी से समझें और अपने दायित्वों में उनका उपयोग कर सकें।

विधानसभा में एआई के संभावित उपयोग में बताया जायेगा कि किस प्रकार एआई विभिन्न क्षेत्रों में मददगार हो सकता है। इसमें एआई उपकरण बिल ड्राफ्ट

करने, कानूनी समस्याओं की पहचान करने और अन्य राज्यों या देशों के कानूनों की तुलना करने में सक्षम हैं। एआई विधायकों की संपत्तियों या हिੱतों से जुड़े संभावित टकरावों की जांच कर सकता है।

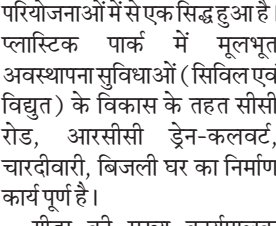
सोशल मीडिया, सर्वेक्षण और याचिकाओं के माध्यम से एआई नागरिकों की राय को विश्लेषित कर सकता है। किसी भी प्रस्तावित कानून के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का प्युानुमान लगाया जा सकेगा।

एआई पुराने दस्तावेजों, बहसों और रिपोर्टों को क्रमबद्ध कर खोज योग्य बना सकता है। भाषणों और दस्तावेजों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में त्वरित अनुवाद संभव होगा। एआई डैशबोर्ड के माध्यम से सरकारी परियोजनाओं की प्रगति और खर्च की रियल-टाइम निगरानी की जा सकेगी।

प्रशिक्षण में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एआई का प्रयोग

सीएम सिटी में आकार ले रहा प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क

घनश्याम कुमार



परियोजनाओं में से एक सिद्ध हुआ है। प्लास्टिक पार्क में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं (सिविल एवं विद्युत) के विकास के तहत सीसी रोड, आरसीसी ड्रेन-कनलर्ट, चारदीवारी, बिजली घर का निर्माण कार्य पूर्ण है।

गौडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक बताती हैं कि प्लास्टिक पार्क में कुछ यूनिट्स में उत्पादन भी शुरू हो चुका है। इन्हीं उत्पादनरत कंपनियों में से 120 करोड़ रुपये के निवेश की तीन इकाइयों का लोकार्पण जल्द ही किया जाना प्रस्तावित है। इसमें प्लास्टिक पैकेजिंग की प्रमुख कंपनी टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी ने 20 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल का भूखंड लेकर 96 करोड़ रुपये का निवेश किया है। दो वर्ष में ही काम पूरा होने के बाद यहां बाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। इस यूनिट में 250 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा गौडा प्लास्टिक पार्क में ओम फ्लैक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को 4150 वर्गमीटर जमीन का आवंटन प्लास्टिक पाइप्स उत्पादन के लिए किया गया है। ओम फ्लैक्स द्वारा 17.00 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 50 लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई है। साथ ही वर्गमीटर पॉली प्लास्ट ने 1196.00 वर्गमीटर जमीन लेकर 7 करोड़ रुपये के निवेश से यूनिट की स्थापना की है। इसमें 25 लोगों को रोजगार मिला है। प्लास्टिक पार्क में केंद्रीय केमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान (सीपेट) द्वारा 16 करोड़ रुपये की लागत से रिकल ट्रेनिंग सेंटर और कामन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाना है। इसके लिए गौडा द्वारा सीपेट को पांच एकड़ भूमि निशुल्क दी गई है। यहां सीपेट द्वारा प्लास्टिक उद्योग में कोशल विकास एवं सेवायोजन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

हर क्षेत्र में आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश के युवा बन रहे आत्मनिर्भर

विश्व युवा कौशल दिवस के समापन समारोह में दिखी विरासत और तकनीक का संगम

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कौशल विकास ढांचे में अब परंपरा और तकनीक एक साथ चल रही हैं, जिससे युवा न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि नवाचार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं।

यह बात बुधवार को विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के समापन समारोह में उभर कर सामने आयी। समापन अवसर पर आयोजित रैलीन चर्चा का पारंपरिक एवं आधुनिक स्किलिंग में संतुलन विषय पर विशेषज्ञों ने पारंपरिक हस्तकला, बुनाई, बर्दईरीग्री जैसे ह्वनर से लेकर डिजिटल रिकल्स, एआई, ऑटोमेशन जैसी आधुनिक तकनीकों के बीच तालमेल स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण विचार साझा किए। कौशल मेले में आयोजित नियोक्ता सम्मेलन में दो



प्रमुख क्षेत्रों के सीईओ और एचआर हेड्स ने मंच से सीधे युवाओं से संवाद स्थापित किया। उन्होंने बताया कि उद्योगों को किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता है, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योग की मांगों के अनुरूप कैसे ढाला जा सकता है। इस संवाद को युवाओं के भविष्य के लिए एक सकारात्मक कदम बताया गया। संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार ने कहा कि यह

सम्मेलन युवाओं के उज्वल भविष्य की दिशा में एक ठोस संवाद है। उन्होंने बताया कि विभाग अधिक से अधिक उद्योग आधारित प्रशिक्षण की सुविधा युवाओं को देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग डॉ. हरिओम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के

नेतृत्व में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राज्य के युवाओं को न केवल पारंपरिक ज्ञान में दक्षता प्राप्त हो, बल्कि उन्हें भविष्य की तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ग्रीन एनर्जी और ऑटोमेशन में भी विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की सोच है कि युवा सिर्फ नौकरी ढूँढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने।

मिशन निदेशक पुलकित खरे ने कहा कि मिशन द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, जिससे प्रशिक्षित युवाओं को उद्योगों में त्वरित प्लेसमेंट मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के आईटीआई संस्थानों को निरंतर उन्नत किया जा रहा है और उनमें तकनीकी नवाचारों को शामिल करते हुए आधुनिक प्रशिक्षण प्रणाली लागू की जा रही है।

पारंपरिक ट्रेड्स के साथ, साथ अब आईटीए एआईए ग्रीन एनर्जी और ऑटोमेशन जैसे फ्यूचरिस्टिक क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। युवाओं को सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी ग्रूनिंग का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सके।

दोपहर की दूसरी पैनल चर्चा में स्किल गैप विश्लेषण मांग बनाम

आपूर्ति पर केंद्रित सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि कौशल की मांग और उसकी पूर्ति के बीच का अंतर कम करने के लिए मिशन के प्रयास व्यावहारिक स्तर पर प्रभावी हो रहे हैं।

वक्ताओं ने बताया कि कैसे कैरियर परामर्श से युवा अपनी रुचि और कौशल के अनुसार करियर चुन सकें हैं और देश के विकास में योगदान दे सकें हैं। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की लोक प्रस्तुतियों ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर नृत्य, गायन, नाटक और कविताओं के माध्यम से युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और कुशल उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को सजीव कर दिया।

भारत-नेपाल सीमा पर जाली परमिट से बस संचालन पर योगी सरकार सख्त कड़ी जांच शुरू, परिवहन विभाग द्वारा तीन जिलों में करायी जायेगी एफआईआर वरिष्ठ संवाददाता (vol)

लखनऊ। भारत, नेपाल सीमा पर कुछ निजी बसों द्वारा कूटरचिंत (जाली) परमिट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मार्ग पर अवैध रूप से संचालन पर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है। इन गंभीर मामलों को संज्ञान में लेते हुए परिवहन आयुक्त ने त्वरित कड़े कदम उठाए हैं। एफआरआरओ लखनऊ तथा एएसएबी ने सूचित किया कि कई बसों द्वारा नेपाल सीमा पर ऐसे परमिट प्रस्तुत किए गए हैं, जो सतही रूप से संभागीय परिवहन अधिकरण द्वारा जारी प्रतीत हो रहे थे, किंतु ज्ञान में यह पूर्णतः जाली वा वैधानिक अधिकार क्षेत्र से परे पाए गए। इस पर सख्त योगी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार में किया।
तीन जनपदों में जाली परमिट की हुई पुष्टि :
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि अब तक तीन जनपदों (अलीगढ़, बागपत व महाराजगंज) में स्पष्ट रूप से जाली परमिट की पुष्टि हो चुकी है। यहां संबंधित एआरटीओ ने प्रमाणित किया कि ऐसा कोई परमिट कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया। इस संबंध में एफआईआर

जाली दस्तावेजों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा नियंत्रण के साथ खिलवाड़ बढ़ाई नही किया जाएगा।
दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही फेसलेस परमिट प्रणाली की कार्यप्रणाली में भी आवश्यक तकनीकी सुधार की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारत सरकार को लिखा गया है।
ब्रजेश नारायण सिंह, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश

दर्ज कराने के साथ दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई को कइया गया।
परिवहन आयुक्त ने डीजीपी को लिखा पत्र :
इसके अतिरिक्त गोरखपुर, इटावा एवं औरैया जैसे जनपदों में भी ऐसे परमिट प्रस्तुत किए गए हैं, जो प्रथम दृष्टया भारत, नेपाल जाली परिवहन समझौता, 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन करने हैं। गोरखपुर प्रकरण में विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन आयुक्त ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को पत्र निर्गत नहीं किया गया। इस संबंध में एफआईआर

एसटीएफ से जांच कराए जाने का अनुरोध किया गया है। नेपाल के लिए यात्रियों के साथ निजी बस संचालन हेतु परमिट केवल गंतव्य देश की दूतावास/कांसुलेट द्वारा ही में जारी किया जाना वैध है। इस परिप्रेक्ष्य में अथवा 30 अथवा 31 फॉर्म में जारी कोई भी परमिट अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने हेतु वैधानिक रूप से अमान्य है। यह स्पष्ट इसलिए आवश्यक है ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे और सभी संबंधित एंजेंसाियां नियमों की सही व्याख्या करें।

गौरतलब है कि इन मामलों में कुछ परमिट ऐसे भी हैं जो पोर्टल की अंती अग्रुवल प्रणाली के माध्यम से जारी हुए प्रतीत होते हैं, जिसमें वाया कॉलम को मैनुअली भरने की छूट होने से नेपाल जैसे स्थान दर्ज किए गए हैं। परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश, जिस में ठठक को स्पष्ट थक फ्लो भेजा गया था, द्वारा पूर्व निर्देश दिया गया था कि ऐसे कॉलम में केवल पूर्व-निर्धारित ड्रॉपडाउन सूची के विकल्प ही चयनित हो सकें, किन्तु यह व्यवस्था आंशिक रूप से ही लागू की गई। इससे ऐसे परमिट पोर्टल से स्वतः जनरट हो सके, जो अब गंभीर दुरुपयोग की श्रेणी में आ गए हैं।

सड़क पर रस्सी बांधकर पेड़ काटने से युवक की मौत पर हंगामा

शव रखकर प्रदर्शन और नारेबाजी, नगर निगम ने दी चार लाख की मदद

फैजुल्लागंज के नौबस्ता मोहल्ले में खुले नाले से गुजरना मजबूरी

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। पीजीआई इलाके में मंगलवार को नगर निगम की ओर से बीच सड़क पर रस्सी बांधकर पेड़ काटने के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा, तो परिजन और ग्रामीण भड़क गए। उन्होंने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साए लोगों ने शव को मोहनलालगंज के गोपाल खेड़ा पुल पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया। एसीपी और एसडीएम के समझाने पर करीब डेढ़ घंटे बाद शव को सड़क से हटाया। अब घर के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नगर निगम कर्मियों पर मुकदमा और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाने के लिए अड़े रहे। गुस्साए परिजन शव को चारपाई पर रखकर सड़क जाम करने के लिए जाने



लगे तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। एसीपी और एसडीएम के समझाने पर करीब डेढ़ घंटे बाद शव को सड़क से हटाया। उसके बाद शव को घर ले गए। वृंदावन सेक्टर नौ मामा चौराहा के पास मंगलवार को नगर निगम की ओर से पेड़ों की कटाई-छटाई चल रही थी। सड़क पर आवाजाही बंद करने के लिए सौ मीटर दूर एक रस्सी बांध दी थी। मोहनलालगंज के गोपाल खेड़ा निवासी 24 वर्षीय अनुज कश्यप बाइक

से फिलपकार्ट की डिलीवरी करने जा रहे थे। रस्सी में फंसकर वो गिरकर घायल हो गए थे। उनकी मौत हो गई थी। मृतक अनुज के भाई सोनू कश्यप ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई को दोपहर करीब डेढ़ बजे छोटा भाई अनुज डिलीवरी देने जा रहा था। पीजीआई थाना क्षेत्र में मामा चौराहा के पास नगर निगम की ओर से पेड़ों कटाई-छटाई चल रही थी। करीब सौ मीटर पहले दो खंभों के सहारे सड़क पर रस्सी बांध दी

थी। रस्सी के पास बैरकिडिंग नहीं की थी, न ही सावधान करने संबंधी कोई सूचना दी थी। इसकी वजह से उनका भाई रस्सी की चपेट में आकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। भाई की मौत के जिम्मेदार रस्सी बांधने वाले नगर निगम के कर्मचारी हैं। उनकी शिकायत पर नगर निगम के अज्ञात कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। नगर निगम अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, अरुण गुप्त और उद्यान अधीक्षक शशिकांत दोपहर बाद गोपाल खेड़ा गांव पहुंचे। यहां पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनको चार लाख रुपये की आर्थिक मदद दी। अपर नगर आयुक्त ने बताया मुख्यमंत्री राहत कोष से पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद के लिए प्रार्थना पत्र भी भेजा जाएगा। अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ने कहा नगर निगम लापरवाह कर्मियों से सख्त कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नगर निगम में संविदा पर नौकरी दी जाएगी। एक जांच कमेटी बनाकर पूरे प्रकरण की जांच भी कराई जाएगी।



इस असुरक्षित रास्ते से गुजरते हैं। बारिश के मौसम में यह और भी फिसलन भरा और जानलेवा हो जाता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस नाले को फौरन ढका जाए या उस पर मजबूत पुलिया बनाई जाए, ताकि किसी अनहोनी से पहले इसकी सुध ली जा सके। यहां के लोगों का कहना है कि अब तक कई जानवर इस खुले नाले में गिरकर घायल हो चुके हैं, कुछ की तो मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके नगर निगम की लापरवाही जस की तस बनी हुई है। इतना ही नहीं स्थानीय निवासियों ने पाषाण पंथी आरोप लगाते हुए

कहा कि उन्होंने बार-बार मदद मांगी, लेकिन कभी निरीक्षण तो हुआ, कोई समाधान नहीं मिला। क्षेत्रीय विधायक नीरज बोगरा के नाम भी कई बार शिकायतें की गईं, मगर हालात अब तक नहीं बदले। लोगों का कहना है कि शिकायतें दर्ज कराईं, बारिश के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, लेकिन अब तक केवल आशवासन ही मिले हैं, काम शुरू नहीं हुआ। इलाके में मौजूद पाषाण पंथी और जिम्मेदार विभाग इस खतरनाक हालात को देखकर भी चुप्पी साधे हुए हैं, मानो वे किसी हादसे का इंतजार कर रहे हों। फैजुल्लागंज में जल निकासी के लिये नालियां नहीं बनी हैं। घरों का पानी रास्तों और खाली प्लाटों में भर रहा है। कई जगह सीवर लीकेज होने की वजह से यह गंदा पानी भी खाली प्लाट में भर रहा है। जलभराव हो गया है।

267 सुएज व जलकल कर्मियों को मिला आयुष्मान कार्ड



विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। इंद्रिया गांधी प्रतिष्ठान में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित नमस्ते दिवस के राष्ट्रीय समारोह में सुएज इंडिया एवं जलकल विभाग ने प्रभावी भागीदारी दर्ज की। यह आयोजन देशभर के सफाईकर्मियों और कचरा बीनने वालों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को समर्पित रहा। सुएज, जो लखनऊ में वन सिटी वन ऑपरेटेड परियोजना के तहत जलकल विभाग के साथ साझेदारी में कार्यरत है, ने इस अवसर पर अपने 267 सफाई

कर्मचारियों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ा। इससे पहले भी सुएज ने पिछले एक वर्ष में 840 से अधिक कर्मचारियों को नमस्ते योजना के अंतर्गत पंजीकृत कराया है। इस आयोजन के दौरान सुएज एवं जलकल विभाग के कर्मचारियों को व्यावसायिक सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए भी सम्मानित किया गया। उन्हें पीपीई किट व अन्य सुरक्षा उपकरण प्रदान किए गए, जिससे सुरक्षित व यंत्रिकृत स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके। इस मौके पर कंपनी के प्रतिनिधियों ने

एलडीए ने 177 किसानों को लॉटरी से आवंटित किये व्यावसायिक चबूतरे

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। जानकीपुरम नगर प्रसार योजना के अंतर्गत अधिग्रहित की गयी भूमि के प्रभावित किसानों को एलडीए ने सावन के मौके पर बड़ा तोहफा दिया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर बुधवार को प्राधिकरण भवन के बारादरी लॉन में पारदर्शी प्रक्रिया के तहत करायी गयी लॉटरी में 177 पात्र किसानों को जानकीपुरम में व्यावसायिक चबूतरे आवंटित किये गये।



अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण ने जानकीपुरम नगर प्रसार योजना विकसित करने के लिए ग्राम-मोहिल्लापुर, खरामपुर जमीर, पहाड़पुर, अकिलपुर, भिटौली खुर्द, बटहा सबौली, सेमरा गौड़ी, मोहिद्धीनपुर, सिकन्दरपुर इनायत अली, खलीलाबाद एवं जाहेंदपुर को जमीन अधिग्रहित की थी। इससे प्रभावित किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें व्यावसायिक चबूतरे आवंटित किये

जाये थे। जिसके लिए कई किसानों ने आवेदन किया था। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने लंबे अरसे से लॉबित किसानों की इस मांग का संज्ञान लिया। उन्होंने जानकीपुरम में सीतापुर रोड पर रेलवे लाइन के किनारे प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर से अवेध कब्जे हटवाकर 177 व्यावसायिक चबूतरे सृजित कराये।

साथ ही आवेदनों की पुनः जांच करारकर जल्द से जल्द चबूतरे की लॉटरी कराने के निर्देश दिए। जिसके अनुपालन में बुधवार को प्राधिकरण भवन के बारादरी लॉन में 829 पात्र किसानों के मध्य चबूतरे की लॉटरी करायी गयी। इस दौरान किसानों के हाथों से ही लॉटरी की पंचियां निकलवायी गयीं। पारदर्शी प्रक्रिया के तहत करायी गयी इस लॉटरी के माध्यम से 177 पात्र किसानों के पक्ष में चबूतरे का आवंटन किया गया। इस मौके पर जौनल अधिकारी सगीता रावत और अधिशासी अभियंता मनोज सागर समेत व्यावसायिक सेल व अर्जन अनुभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

यूपी में विशिष्ट वन होंगे स्थापित, एकलव्य वन से शुरु

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार एक दिन में 37,21,40,925 से अधिक पौधे रोपने वाले यूपी में अब विशिष्ट वनों की स्थापना होगी। राज्य स्तरीय आयोजनों को लेकर वन विभाग ने अंतिम तिथि भी जारी कर दी है। यह कार्यक्रम पूरे वर्षा काल के दौरान चलेगा। अलग-अलग प्रभागों को राज्य स्तर पर मुख्य आयोजन कर अलग-अलग वन स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। 18 जुलाई को पीलीभीत से एकलव्य वन की स्थापना के साथ ही विशिष्ट वनों की श्रृंखला का आगाज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्तरीय सभी विशिष्ट पौधरोपण की स्थापना व संरक्षण को लेकर वन विभाग को प्रमुख वन संरक्षक व प्रधान मुख्य वन संरक्षक व

शक्ति वन, एकलव्य वन, ऑक्सी वन, त्रिवेणी वन, अटल वन, गोपाल वन, एकता वन, पवित्र धारा पौधरोपण, भाई-बहन पौधरोपण, शौर्य वन, एक पेड़ गुरु के नाम पौधरोपण के साथ ही अन्य क्रियाकलापों (सहजन भंडारा, औद्योगिक इकाइयों की भागीदारी से रोपण) पर भी जोर दिया है। 19 जुलाई को बरेली में ऑक्सी वन, 21 जुलाई को लखनऊ में शक्ति वन, 23 जुलाई को प्रयागराज में त्रिवेणी वन, 25 जुलाई को आगरा में अटल वन, 26 जुलाई को सहजन भंडारा, 27 जुलाई को मथुरा में गोपाल वन, 31 जुलाई को मेरठ में एकता वन की स्थापना होगी। रक्षाबंधन (9 अगस्त) पर भाई-बहन पौधरोपण, 15 अगस्त को शौर्य/सिंह वन और 5 सितंबर को 'एक पेड़ गुरु के नाम' पर लगाया जाएगा।

टीजी टू को फील्ड पर भेजा जाये : रिया केजरीवाल राजस्व वसूली में फिसडी सीतापुर के तीन जेई को चार्जशीट

समरेश पति त्रिपाठी

लखनऊ। टीजी टू को फिल्ड का कार्य कराया जाना चाहिए। बिजली कर्मचारियों की बायोमेट्रीक 90 प्रतिशत हो तभी वेतन दिया जाना चाहिए। टर्न-अप न्यूनतम 10 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। ये बातें मथुरा चाल एमडी रिया केजरिवाल ने सीतापुर के जेई, एसडीओ, एक्सीएन और मुख्य अभियंता के सामने कहा। उन्होंने मुख्य अभियंता (वितरण) सीतापुर को प्राथमिकता के आधार पर आदेशित किया गया कि जुलाई माह में किसी भी कामिंक का वेतन बिना बायोमेट्रिक अटेंडेन्स के निर्गत ना किया जाये। उन्होंने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रत्येक 11 केवी पोषक वार उपभोक्ताओं का टर्न-अप न्यूनतम 10



प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित कराये। अन्यथा की स्थिति में विभागीय कार्यवाही की जा सकती हैं। एमडी ने सीतापुर के तीन जूनियर इंजीनियरों को राजस्व वसूली में फिसडी होने पर चार्जशीट देने के लिए निर्देश दिया है। इसमें रामपुर मथुरा, भवानीपुर (ग्रामीण), पोखरा कला उपकेंद्र के जूनियर इंजीनियर पर कार्यवाई होगी। एमडी बुधवार को बिजली सप्लाई व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सीतापुर जेन का निरीक्षण किया। इस दौरान एमडी ने संबंधित अधिकारियों को टर्न-अप बढ़ाने एवं राजस्व वसूली में वृद्धि करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि फुके ट्रांसफार्मरों को बदलकर तुरंत बिजली सप्लाई बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में राजस्व वसूली को बढ़ाया जाना चाहिए। ट्रांसफार्मर किस कमी से फूंक रहे है इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इस दौरान मुख्य अभियंता (वितरण), अधीक्षक अभियंता सीतापुर, एक्सीएन, एसडीओ और जेई सहित अधिकारी मौजूद थे।

बेटियों को सशक्त बनाना ही राष्ट्र निर्माण है : डॉ. राजेश्वर सिंह नयी रफ्तार

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। मैं तारा शक्ति केंद्र क्यों खेल रहा हूँ, बालिका विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी क्यों स्थापित कर रहा हूँ, हर गांव में बालिका खेल क्लब क्यों बना रहा हूँ, दूरस्थ लतीफ नगर गांव में बालिका डिग्री कॉलेज का निर्माण क्यों कर रहा हूँ, और युवतियों को निःशुल्क डिजिटल प्रशिक्षण क्यों दिला रहा हूँ। क्योंकि बेटियों को सशक्त बनाना केवल सामाजिक सुधार नहीं, यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। बुधवार को सरोजनीनगर से भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सशक्त, दूरदर्शी और तथ्य-आधारित संदेश साझा करते हुए बताया कि भारत को अगे ले जाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य है। उन्होंने राष्ट्रीय और वैश्विक आंकड़ों का हवाला देते हुए महिला सशक्तिकरण को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक प्रगत से सीधे जोड़ा।



उन्होंने बताया कि मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार, यदि भारत लैंगिक असमानता को पाते तो 2025 तक जीडीपी में 770 डॉलर बिलियन की वृद्धि संभव है। लेकिन वर्ल्ड बैंक (2024) के अनुसार, आज भी केवल 23% महिलाएं औपचारिक कार्यबल में शामिल हैं। महिलाओं की भागीदारी कोई विश्वोपाधिकार नहीं, यह भारत की अर्थिक अनिवार्यता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में व्यापक प्रभाव यूनेस्को के अनुसार, एक शिक्षित महिला अपने बच्चों को शिक्षित करने की संभावना दो गुना अधिक होती है। जहां महिला साक्षरता दर 70.3% है, वहीं पुरुषों की

84.7%, यह अंतर चिंताजनक है। एक महिला को शिक्षित करना, एक पीढ़ी को शिक्षित करना है। महिलाएं अपनी आय का 90% परिवार में पुनर्निवेश करती हैं, जिससे ग्रामीण, दलित और आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक बदलाव आता है। किसी परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का सबसे तेज तरीका है झ उसकी महिला को सशक्त बनाना। भागीदारी और शासन की मजबूती लोकसभा में आज भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 15% है। लेकिन अध्ययन बताते हैं कि महिला नेता स्वास्थ्य, शिक्षा और जमीनी विकास में अधिक निवेश करती हैं। जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, तो समाज सुनता है और अंगे बढ़ता है। सुरक्षित, सशक्त और संगठित भारत जहां लैंगिक समानता अधिक है, वहां अपराध दर कम, शैक्षणिक स्तर उच्च, और सामाजिक समरसता मजबूत होती है। रकोई भी राष्ट्र तब तक नहीं उठ सकता, जब तक वह अपनी

नालों की मरम्मत पर कोटा खर्च करने को तैयार नहीं पाषर्ष

लखनऊ। पाषर्षद नालों की मरम्मत पर अपना कोटा खर्च करने को तैयार नहीं हैं। बुधवार को भाजपा पाषर्षदों ने नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ बैठक की जिसमें 15वें वित्त मद से नालों का काम कराने का सुझाव दिया और उसके लिए बजट मंजूर करने के लिए महापौर को प्रस्ताव देने की बात रखी। बुधवार करीब 15 पाषर्षदों ने नगर आयुक्त गौरव कुमार से उनके कार्यालय में बैठक की। जिसमें पाषर्षदों ने नालों की मरम्मत और रुके विकास कार्य कराने की बात उठाई। जिस पर नगर आयुक्त ने कहा कि नालों की मरम्मत पर करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक का बजट खर्च होगा। इसी तरह सड़कों की मरम्मत पर भी इतना ही बजट पैच वर्ष पर खर्च होगा लेकिन उतना पैसा अभी नगर निगम के पास नहीं है। इस पर पाषर्षद चुप्पी साध गए। किसी ने यह नहीं कहा कि कोटे का पैसा नालों की मरम्मत में लगाया दिया जाए बल्कि यह सुझाव दिया कि 15वें वित्त से बजट खर्च किया जाए।

जेपीएनआईसी की कमेटी भंग, म्यूजियम ब्लॉक चलायेगा एलडीए

लखनऊ। जेपीएन इंटरनेशनल सेंट्र के संचालन के लिए सरकार के एलडीए को जिम्मेदारी सौंपने के बाद कार्यवाई शुरू कर दी गई है। एलडीए की ओर से पुरानी कमेटी को भंग कर दिया गया है। अब इसके संचालन को कई कमेटी के लिए जल्द ही गवर्निंग बोर्ड की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव करेंगे। वहीं इसके लेआउट में बदलाव भी होगा। सार्थीकेंद्र के संचालन के लिए जल्द टेंडर भी जारी किया जाएगा। एलडीए ने तय किया है कि जेपीएनआईसी का म्यूजियम ब्लॉक खुद प्राधिकरण संचालित करेगा, जबकि बाकी केंद्र का संचालन किसी निजी संस्था को सौंपा जाएगा। इसके लिए बैठक के बाद टेंडर जारी किया जाएगा। साथ ही लेआउट में भी जरूरी बदलाव किए जाएंगे ताकि संचालन में कोई दिक्कत न हो। जेपीएनआईसी के संचालन को लेकर बनने वाली नई कमेटी कई अहम जिम्मेदारियां निभाएगी। यह कमेटी तय करेगी कि कौन-कौन सी सुविधाएं किए पर दी जा सकती हैं, उनका शुल्क क्या होगा, और किन वर्गों को छूट मिलेगी। एलडीए अधिकारियों के मुताबिक, जेपीएनआईसी का लगभग निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब केवल फिनिशिंग टच, लैंडस्केपिंग, फर्निशिंग और तकनीकी उपकरणों की स्थापना बाकी है। यह काम लगभग डेढ़ साल में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद संचालन शुरू किया जा सकेगा।

उत्तराखंड के लोक पर्व हरला के शुभ अवसर पर पर्वतीय महापरिषद, लखनऊ के अध्यक्ष गणेश जीशी के नेतृत्व में परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की और हरला भेंट किया।

अमेरिका ने निर्वासित लोगों को एस्वातिनी भेजा

केप टाउन। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के गोपनीय तृतीय-देश निर्वासन कार्यक्रम के तहत पांच लोगों को अफ्रीकी देश एस्वातिनी निर्वासित कर दिया है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में लोगों को उन देशों में भेजने पर रोक लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया था, जहां से उनका कोई संबंध नहीं है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने आठ लोगों को एक अन्य अफ्रीकी देश दक्षिण सूडान निर्वासित कर दिया था। हालांकि, दक्षिण सूडान की सरकार ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि लश्कराबादी हथियारों को वहन करने वाले इन लोगों को कहां रखा गया है। गृह सुरक्षा विभाग की सहायक मंत्री टुशिया मेकलॉर्घलिन ने मंगलवार देर रात एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि विधानमंडल, जमैका, क्यूबा, यमन और लाओस के पांच नागरिकों को एक विमान से एस्वातिनी भेज दिया गया



है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इन लोगों को कब भेजा गया और इन्हें कहां रखा गया है। मैकलॉर्घलिन ने कहा कि ये सभी लोग दोषी ठहराए गए अपराधी थे और इतने बर्बर व्यक्ति थे कि उनके मूल देशों ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये लोग अमेरिकी समुदायों को आतंकित कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें अमेरिकी धरती से बाहर कर दिया गया है। मैकलॉर्घलिन ने कहा कि इन लोगों को

ट्रंप प्रशासन ने 10 राज्यों में आव्रजन कोर्ट के 17 न्यायाधीशों को किया बर्खास्त

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा आव्रजन कोर्ट के बड़े पैमाने पर निर्वासन की प्रक्रिया को तेज किए जाने के बीच 10 राज्यों की आव्रजन अदालतों के 17 न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन्होंने न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने यह जानकारी दी। आव्रजन न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल इंजीनियर्स ने एक वक्तव्य में कहा कि शुकवार को 15 और सोमवार को दो न्यायाधीशों को बिना कोई कारण बताए बर्खास्त कर दिया गया। संगठन ने कहा कि इन न्यायाधीशों को बर्खास्त किया गया है वे कैलिफोर्निया, इल्लिनॉय, लुइसियाना, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, ओहायो, टेक्सास, यूटा और वर्जीनिया की आव्रजन अदालतों में सेवारत थे। संगठन के अध्यक्ष मैट बिम्स ने कहा कि यह बेहद ही निंदनीय और जनहित के विरुद्ध है। एक तरफ संसद ने 800 आव्रजन न्यायाधीशों को नियुक्ति का मंजूरी दी है, दूसरी ओर बड़ी संख्या में आव्रजन न्यायाधीशों को बिना किसी कारण के हटाया जा रहा है, यह बेतुका है...। इन न्यायाधीशों को हटाए जाने का कारवाई ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीतियों के तहत अधिकारी बड़ी संख्या में आव्रजन कोर्टों को गिरफ्तार कर रहे हैं और पीछे पक्ष अदालतों का रुख कर रहे हैं।

संक्षेप तेलंगाना मॉडल पर जातिगत गणना करार के केंद्र : कांग्रेस

बेंगलूरु। कांग्रेस की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सलाहकार परिषद की बुधवार को हुई बैठक में केंद्र से तेलंगाना जाति सर्वेक्षण के मॉडल के आधा पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित जातिगत गणना करार का आह्वान किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धमैया की अध्यक्षता में यहां हुई दो दिवसीय बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। सिद्धमैया ने परिषद में पारित प्रस्तावों को बेंगलूरु घोषणा नाम देते हुए कहा कि जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति और जाति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरा प्रस्ताव आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को समाप्त करने का था, जिससे शिक्षा, सेवा, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में ओबीसी के लिए उपयुक्त आरक्षण सुनिश्चित हो सके। सिद्धमैया ने कहा कि बैठक में पारित तीसरे प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुसार निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए। परिषद की बैठक में नेताओं ने इन मांगों पर जोर देने के लिए एक तीव्र और आक्रामक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का भी संकल्प लिया। सलाहकार परिषद ने सर्वप्रथम तेलंगाना मॉडल पर जातिगत गणना को समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद दिया।

हिमंत शर्मा को निश्चित ही जेल भेजा जायेगा : राहुल गांधी

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यहां प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के दौरान कहा है कि मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से जेल भेजा जाएगा। शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता यह भूल गए कि वह स्वयं देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में जमानत पर हैं। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखित में ले लीजिए, हिमंत विश्व शर्मा को निश्चित रूप से जेल भेजा

फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी अगस्त के बाद ईरान पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध करेंगे बहाल

संयुक्त राष्ट्र। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने इस बात पर सहमति जताई है कि अगर परमाणु समझौते पर कोई ठोस प्रगति नहीं होती है तो अगस्त के अंत तक ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के कड़े प्रतिबंध बहाल कर दिए जाएंगे। दो यूरोपीय राजनयिकों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र में तीनों देशों के राजदूतों ने मंगलवार को जर्मनी स्थित संयुक्त राष्ट्र मिशन में ईरान के साथ संभावित समझौते और प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर चर्चा की। दो अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, सोमवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर हुई बातचीत में भी यह मुद्दा उठा। अधिकारियों और राजनयिकों ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर यह जानकारी दी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने रूबियो और तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बाद कहा कि सभी ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान

निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि का मामले में अदालत ने शिकायतकर्ता पर लगाया जुर्माना

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा पर बुधवार को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मित्रा आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक सोमनाथ भारतीय की पत्नी हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने कहा, शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है और यहां तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायाधीश ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की सुविधानुसार तारीख और समय तय किया गया था। उन्होंने कहा कि उपस्थित न होने के कारण शिकायतकर्ता (मित्रा) पर



5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जिसे सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन में जमा करना होगा। न्यायाधीश ने मित्रा को जवाब दखिल करने एवं दलालें पेश करने का आर्तिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख तय की। शिकायत में दावा किया गया है कि सीतारमण ने 17 मई, 2024 को एक संवाददाता सम्मेलन में

अपमानजनक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए जिनका एकमात्र उद्देश्य भारती की प्रतिष्ठा को धूमिल करना एवं आम चुनावों में उनकी जीत की संभावनाओं को कमजोर करना था। ये बयान केवल शिकायतकर्ता और उसके पति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दिए गए थे तब 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार को राजनीतिक लाभ और शिकायतकर्ता के पति को राजनीतिक नुकसान हो। इसमें कहा गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता एवं उनके पति के वैवाहिक संबंधों में कलह का जिक्र किया लेकिन उनके पुनर्मिलन और खुशी-खुशी साथ रहने की जानकारी नहीं दी।

कांग्रेस छोड़कर भागने वाला व्यक्ति अब असम का सीएम : खरगे

चायगांव (असम)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि पार्टी ने भाजपा को असम में सरकार बनाने के लिए अपना सदस्य उधार दिया था। खरगे ने राज्य की एक दिवसीय यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को बैठक को संबोधित करते हुए कहा, जो व्यक्ति कांग्रेस छोड़कर भाग गया था, वह अब असम का मुख्यमंत्री है। शर्मा 2015 में भाजपा में शामिल होने से पहले असम की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार पर ब्रह्मचर में लिखत होने का आरोप लगाते हुए खरगे ने कहा कि लोगों से अन्याय करने वालों को जेल भेजा जाएगा। उन्हें अब जेलों की मरम्मत करवानी चाहिए, क्योंकि उन्हें वहीं रहना होगा। उन्होंने दावा किया कि असम में अवैध प्रवासियों का पता लगाने की आड़



में लोगों को धमकाया जा रहा है और वे अगले साल होने वाले चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले सरकार को सबक सिखाएंगे। असम में बेदखली अभियान पर खरगे ने कहा कि यदि कांग्रेस राज्य में सरकार बनाती है तो वह मकानों का पुनर्निर्माण करेगी और भाजपा सरकार की

विफल करने का आग्रह किया। खरगे ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह असम में बच्चों के लिए शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और चाय बागान श्रमिकों के लिए अधिकतम मजदूरी को गारंटी देगी। उन्होंने यह दावा भी किया कि दलितों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को सतर्क रहना होगा, वरना केंद्र की भाजपा सरकार उनके आरक्षण को छीन लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि मोदी ने पांच दिनों में पांच देशों का दौरा किया, लेकिन उन्हें हिसास्रत मणिपुर आने के लिए दो घंटे भी नहीं मिले। उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए लोगों को एकजुट होना होगा। उन्होंने दावा किया कि संविधान हमारे लोकतंत्र का आधार है। आरएसएस और भाजपा इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

गाजा में राहत सहायता वितरण केंद्र पर 20 फलस्तीनियों की मौत



तेल अवीव। गाजा में इजराइल समर्थित अमेरिकी सहायता संगठन ने बुधवार को कहा कि राहत सहायता वितरण केंद्र के निकट 20 फलस्तीनियों की मौत हुई है। इससे पहले, अस्पताल के अधिकारियों ने बताया था कि इजराइल हमलों में 11 बच्चों समेत 41 लोगों की मौत हुई है। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फंड (जीएचएफ) ने कहा कि दक्षिण गाजा के खान यूनिस् शहर में स्थित वितरण केंद्र पर 19 लोगों की मौत भगदड़ में कुचलने से हुई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय व प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जीएचएफ कार्यकर्ताओं ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दारे, जिससे भगदड़ मच गई। मंत्रालय ने कहा कि यह पहली बार है जब राहत सहायता स्थलों पर भगदड़ मचने से लोगों की मौत हुई है। साथ ही, जीएचएफ ने पहली बार अपने किसी राहत सहायता वितरण स्थल पर मौत होने की पुष्टि की है। हालांकि, फलस्तीनी प्रत्यक्षदर्शियों, स्वास्थ्य अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का कहना है कि खाद्य सामग्री लेने के लिए इन केंद्रों की ओर जाते समय सैकड़ों लोग मारे गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि स्टेन ग्रेनेड और मिच स्प्रै के कारण अफरा-तफरी मच गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भीड़ में यह संदेश फैलने के बाद भगदड़ मच गई कि कोई राहत सहायता वितरित नहीं की जाएगी। निकटवर्ती शहर रफह के निवासी उमर अल-नजर ने कहा कि लोगों को संभवतः आंसू गैस के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने हमारे खिलाफ स्टेन ग्रेनेड और मिच स्प्रै का इस्तेमाल किया।

इंटरनेट... फिलम 'वॉर 2' का नया पोस्टर जारी



मुंबई। श्रुतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वॉर 2' का बुधवार को एक और पोस्टर जारी कर दिया गया है। नए पोस्टर में श्रुतिक रोशन, किरारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं, फिल्म को लेकर मेकर्स का कहना है कि यह इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में से एक साबित होगी। पोस्टर में श्रुतिक रोलवार के साथ

लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नवभारत टाइम्स और जूनियर एनटीआर के बीच जबरदस्त एक्शन के मुताबिक, इस हफ्ते के अंत तक फिल्म वॉर 2 का

कृति सेनन, जावेद जाफरी की बिल्डिंग में घुसा अज्ञात शख्स

मुंबई। कृति सेनन और जावेद जाफरी की बिल्डिंग में एक अज्ञात शख्स घुस आया। वो शख्स सिव्कोरिटी को चकमा देते हुए लिफ्ट तक पहुंचा। उसने लिफ्ट में जाकर तोड़फोड़ की। पुलिस को लिफ्ट का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें वो शख्स कैमरे की तरफ देखते हुए अश्लील इशारे कर रहा है। ये घटना 19 जून को देर रात की बताई जा रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पाली हिल के पॉश इलाके में स्थित हार्ड प्रोफाइल बिल्डिंग संघू पैलेस में देर रात 1 बजे एक शख्स ने पीली कार में गेट नंबर 1 से एंट्री ली थी। सिव्कोरिटी ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि वो 17वीं मंजिल पर रहने वाले परिवार से मिलने आया है। उस फ्लोर के मालिक ने कहा था कि अगर कोई मिलने आता है।

टीवी कमबैक के लिए स्मृति राजनीति से लेगी बैंक ?



मुंबई। स्मृति ईरानी ने अपने आईकॉनिक शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' रीब्रूट के साथ टेलीविजन पर वापसी कर रही हैं। शो का पहला लुक कुछ दिन पहले जारी किया गया था। टीवी पर उनके कमबैक के बाद कई फैस कयास लगा रहे थे कि अब वो राजनीति से ब्रेक लेगी। लेकिन स्मृति ने इन कयासों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। दरअसल, 'क्योंकि सास भी एक फैन ने शो के लिए बधाई देते हुए लिखा टीवी पर वापसी के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है कि यह राजनीति से बस एक छोटा सा ब्रेक होगा।' जवाब में स्मृति ने कहा, कोई ब्रेक नहीं। 125 साल तक मीडिया और राजनीति दोनों में काम किया है।

पंचायत के फैन बने सीजन 4 के डायरेक्टर



मुंबई। मैं टीवीएफ के सारे शो देखता था। पंचायत सीरीज का बहुत बड़ा फैन था। कोविड के दौरान पंचायत सीरीज देखी। इस सीरीज ने मेरे दिल को खूबिया था। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन इस शो को डायरेक्टर करने का मौका मिलेगा। यह कहना है पंचायत 4 के डायरेक्टर अक्षत विजयवर्गीय का। हाल ही में बातचीत के दौरान अक्षत ने पंचायत सीरीज से जुड़ने और करियर को लेकर

दिलचस्प खुलासा किए। इंदौर के पास एक छोटी सी जगह धार है। वहां का रहने वाला हूं। मेरे दादा जी एक्टर बनना चाहते थे। उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन दादा जी के चार भाइयों ने मिलकर धार में सिनेमा हॉल बनवा दिया। मैं बचपन से ही फिल्मों देखते पला बढ़ा हूं। सिनेमा हमारे लिए

BABU BANARASI DAS EDUCATIONAL GROUP

NBA NATIONAL BOARD OF ARCHITECTURE

BBDNIIT (056) - CSE, IT & B.PHARM
BBDITM (054) - CSE, ECE & IT

12500+ More than **1800+** Companies have already hired our Students!
Job offers & still continuing since last 5 years ...

BBD UNIVERSITY | www.bbdu.ac.in

COURSES OFFERED

- Engineering
- Management
- Legal Studies
- Pharmacy
- Architecture
- Dental Science
- Computer Applications
- Basic Sciences
- Education
- Hotel Management
- Agricultural Sciences
- Media & Communication
- Ph.D. in all Disciplines

Highest Package **52.00 LPA** (Microsoft)

Dream Placement **44.15 LPA** (amazon)

Dream Placement **28.88 LPA** (Google)

B.Sc. (Agriculture) 4 Year Full Time Degree Program

- Courses available in Collaboration with IBM
- Minor Degree available in Collaboration with IIT - Mandi

BBDCODS Bachelor of Dental Surgery
www.bbdcods.edu.in (4 Year Course & 1 Year Rotatory Internship) In all 9 Specialties

BBDITM | AKTU CODE - 054 | www.bbditm.ac.in
B.TECH [CSE, CSE(AI&ML), CSE(DS), IT, ECE, ME, EE, CE] MBA & M.TECH

BBDNIIT | AKTU CODE - 056 | www.bbdniit.ac.in
B.TECH [CSE, CSE(AI&ML), CSE(AI), IT, ECE, EE, ME, CE] M.TECH, MBA B.PHARM, M.PHARM, D.PHARM BTEUP CODE- 2746

AMENITIES

- Auditorium (1000+ Seating Capacity)
- Student's Mall & Cafeteria
- Transport & Health Services
- Lord Siddhi Ganesh Temple
- In Campus Bank and ATM
- AC & Non-AC Hostels
- BCCI Approved Cricket Stadium
- BBD 24x7 Security Channel & Wifi Campus
- Fully Wifi Campus

TOP RECRUITERS

amazon Google IBM adani zomato Grob accenture TCS pwc Microsoft Infosys HARMAN adani Capgemini NEWGEN wipro accenture

BBD City, Ayodhya Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226028 India.
f @lkobbd u @bbduiversity www.bbdu.ac.in 0522(619622/23) 0522(6196300/301/302)

